

No. of Printed Pages : 8

MRDE-101

M. A. (RURAL DEVELOPMENT) /

P. G. DIPLOMA IN RURAL

DEVELOPMENT

(MARD/PGDRD)

Term-End Examination

June, 2026

MRDE-101 : RURAL SOCIAL DEVELOPMENT

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

Note : *Attempt all the **five** questions. All questions carry equal marks. Answer to question nos. 1 and 2 should not exceed 800 words each.*

1. Describe the current educational situation of rural children. Highlight the importance of early childhood care and education. 20

Or

Define the concept and causes of bondage.
Discuss women in bondage with special
reference to women in trafficking. 20

2. Discuss the salient features of various
legislations enacted for the protection of
women. 20

Or

Explain the social legislations on scheduled
castes and scheduled tribes. 20

3. Answer any *two* of the following questions in
about **400** words each :

- (a) Discuss the factors contributing to
educational backwardness of rural
women. 10
- (b) Explain the constitutional provisions
enshrined in the Indian constitution for
women. 10
- (c) Describe the meaning, characteristics
and significance of social legislation. 10

4. Answer any *four* of the following questions in about **200** words each :

- (a) Briefly explain the socio-demographic characteristics of rural women. 5
- (b) List the key indicators of women's health and nutritional status. 5
- (c) Explain the process of empowerment. 5
- (d) Enlist the major reasons for the continuation of child labour practice in India. 5
- (e) Enumerate the objectives of ICDS programme. 5
- (f) List some of the constitutional provisions for the protection and upliftment of scheduled castes. 5

5. Write short notes on any *five* of the following in about **100** words each :

- (a) The Gender Empowerment Measure (GEM) 4
- (b) Health and nutritional status of rural children. 4
- (c) Denotified and nomadic tribes 4

- (d) Schemes for the promotion of rural industries 4
- (e) Mental Health Act, 1987 4
- (f) Public Interest Litigation 4
- (g) The Pre-natal Diagnostic Techniques
(Regulation and Prevention of Misuse)
Amendment Act, 2002 4
- (h) Women in local governance 4

MRDE-101

एम. ए. (ग्रामीण विकास) /

ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

(एम. ए. आर. डी. / पी. जी. डी. आर. डी.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2026

एम.आर.डी.ई.-101 : ग्रामीण सामाजिक विकास

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान

हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर (प्रत्येक) 800 शब्दों से

अधिक नहीं होने चाहिए।

1. ग्रामीण बच्चों की वर्तमान शैक्षिक स्थिति का वर्णन कीजिए।

प्रारम्भिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के महत्व पर

प्रकाश डालिए।

20

अथवा

बंधन की अवधारणा और कारणों को परिभाषित कीजिए।
तस्करी में फँसी महिलाओं के विशेष संदर्भ में बंधन में फँसी
महिलाओं पर चर्चा कीजिए। 20

2. महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियमित विभिन्न कानूनों
की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। 20

अथवा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर सामाजिक
विधानों को समझाइए। 20

3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक)
लगभग 400 शब्दों में दीजिए :

(क) ग्रामीण महिलाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन में योगदान
देने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। 10

(ख) महिलाओं के लिए भारतीय संविधान में निहित
संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए। 10

(ग) सामाजिक कानून के अर्थ, विशेषताओं और महत्व
का वर्णन कीजिए। 10

4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर (प्रत्येक) लगभग

200 शब्दों में दीजिए :

(क) ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-जनसांख्यिकीय

विशेषताओं को संक्षेप में समझाइये। 5

(ख) महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति के

प्रमुख संकेतकों की सूची बनाइए। 5

(ग) सशक्तिकरण की प्रक्रिया को समझाइये। 5

(घ) भारत में बाल श्रम प्रथा के जारी रहने के प्रमुख

कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। 5

(ङ) आई. सी. डी. एस. कार्यक्रम के उद्देश्य गिनाइए। 5

(च) अनुसूचित जातियों की सुरक्षा और उत्थान के लिए कुछ

संवैधानिक प्रावधानों की सूची बनाइए। 5

5. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लगभग

100 शब्दों (प्रत्येक) में लिखिए :

(क) लिंग सशक्तिकरण उपाय (जीईएम) 4

(ख) ग्रामीण बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति	4
(ग) विमुक्त और खानाबदोश जनजातियाँ	4
(घ) ग्रामीण उद्योगों का बढ़ावा देने वाली योजनाएँ	4
(ङ) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987	4
(च) जनहित याचिका	4
(छ) प्रसवपूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2002	4
(ज) स्थानीय प्रशासन में महिलाएँ	4

x x x x x